



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934

No. 135]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

सं. 02(आर ई-2012)/2009—2014

विषय : इलैक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी) व्यवस्था आरंभ करना ।

फा. सं. 01/02/110/एम 12/ईडीआई.—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्रस्तुत करने की इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया आरंभ करते हैं ।

2. वर्तमान में, विदेश व्यापार नीति की विविध स्कीमों के तहत लाभों का दावा करने के लिए, निर्यातकों को प्रक्रिया पुस्तक खंड-1, (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 22क (वास्तविक निर्यात) और 22ख (मान्य निर्यात) के मौजूदा प्रपत्रों में बैंकों से बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्राप्त करना होता है और उसे व्यक्तिगत रूप से विदेश व्यापार महानिदेशालय को जमा करना होता है । इलैक्ट्रानिक बीआरसी व्यवस्था के आरंभ होने के बाद बैंक व्यक्तिगत रूप से प्राप्त और जमा बीआरसी को प्रतिस्थापित करते हुए डीजीएफटी सर्वर को इलैक्ट्रानिक रूप से बीआरसी जारी और हस्तांतरित करेगा । संशोधित प्रक्रिया, तकनीकी दिशानिर्देशों सहित डीजीएफटी की वेबसाइट dgfi.gov.in पर 'ई-बीआरसी' आइकन के तहत उपलब्ध है ।

3. तथापि, सरल अन्तरण सुनिश्चित करने के लिए इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि तक वास्तविक बीआरसी की मौजूदा व्यवस्था के साथ-साथ ई-बीआरसी की नई व्यवस्था जारी रहेगी । इसके बाद, डीजीएफटी को इलैक्ट्रानिक रूप से 'ई-बीआरसी' जारी करना और हस्तांतरण करना अनिवार्य होगा ।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से एक माह के बाद बीआरसी की वास्तविक प्रति जमा करना अनिवार्य नहीं होगा । 'ई-बीआरसी' से सौदा लागत और समय की बचत होगी ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th June, 2012

No. 02(RE-2012)/2009—2014

Subject : Introduction of electronic Bank Realization Certificate (e-BRC) system.

F. No. 01/02/110/AM 12/EDI.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2009—2014, the Director General of Foreign Trade introduces an electronic procedure of filing of Bank Realization Certificate (BRC).

2. At present, for claiming benefits under various schemes of Foreign Trade Policy, exporters have to obtain Bank Realisation Certificate (BRC) from banks in the existing formats prescribed at Appendix 22A (physical exports) and 22B (deemed exports) of Handbook of Procedure -Vol. 1 (Appendices and Aayaat Niryaat Forms) and submit the same to the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) manually. With the introduction of electronic BRC system, banks will issue and transmit BRC's electronically to DGFT's server replacing the manual mode of obtaining and submitting BRC. The revised process flow with technical guidelines are available on the DGFT's website dgft.gov.in under the 'e-BRC' icon.

3. The existing system of physical BRC along with the new system of 'e-BRC' will however, run concurrently for a period of one month from the date of issue of this Public Notice for ensuring smooth transition. Thereafter, issuance and transmission of 'e-BRC' to DGFT in electronic form would be mandatory.

Effect of Public Notice :

Submission of physical copy of BRC for claiming benefit of FTP will not be mandatory after one month from the date of issue of this Public Notice. The 'e-BRC' will reduce the transaction cost and time.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade